
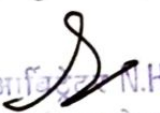
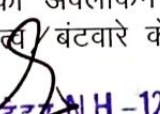


<p>तारीख हुकम</p>	<p>इनका मोर्चा NH-12 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>7/6/24</p>	<p>अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10.7.2024 को पेश हो।</p>	
<p>10/7/24</p>	<p>अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। बहस सुनी गई। अभिभाषक एन0एच0 12 व अभिभाषक (विवेक सूद) ने आदेश दिनांक से पूर्व लिखित बहस पेश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.7.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  आविर्देटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.) </p>	
<p>10/7/24</p>	<p>अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। अभिभाषक एन0एच0 12 व अभिभाषक (विवेक सूद) ने लिखित बहस पेश की। आज हम अन्य राज कार्य में व्यस्त रहने से आदेश नहीं सुना सके। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.8.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  आविर्देटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.) </p>	
<p>1/8/24</p>	<p>अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस निवेदन किया कि खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम गुंसी का अवाई संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 अनेक व्यक्तियों के नाम जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण कि हिस्से की भूमि ही अवाप्त की गई है। अन्य व्यक्तियों कि भूमि राहोली रोड पर स्थित है। इस कारण उनके हक मे मुआवजा राशि का अवाई नहीं दिया जा सकता है। मुआवजा का निर्धारण मौके पर काबिज भूमि के अनुपात मे निर्धारण कर अलग-अलग चैक बनाया जावे।</p> <p>भारतीय राजमार्ग राष्ट्रीय प्राधिकरण के अभिभाषक ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अवाई संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त जारी किया गया है। प्रार्थीगण को 3 ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी,परन्तु प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कि है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज किया जावे।</p> <p>अभिभाषक (विवेक सूद)ने दौराने बहस मे निवेदन किया कि अवाई संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त जारी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा सिविल प्रकृति के विवाद के संबंध मे प्रस्तुत किया गया है,जिसका क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है,बल्कि धारा 3 (एच)(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत माननीय जिला न्यायाधीश टोंक को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य स्वामित्व/बंटवारे के संबंध मे विवाद है।</p> <p style="text-align: right;">  आविर्देटर N.H.-12 (जिला कलेक्टर) टोंक (राज.) </p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में

अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क है कि अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 अनेक व्यक्तियों के नाम जारी किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण कि हिस्से की भूमि ही अवाप्त की गई है। अन्य व्यक्तियों कि भूमि राहोली रोड पर स्थित मुआवजा का निर्धारण मौके पर काबिज भूमि के अनुपात में निर्धारण कर अलग-अलग चैक बनाया जावे, परन्तु अवार्ड पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वंत 2059-2062 वाके ग्राम गुंसी तहसील निवाई में खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा भूमि में कुल 16 खातेदारान का नाम है। खातेदारान के मध्य में उक्त भूमि का तकास्मा/बंटवारा नही होने के कारण सक्षम प्राधिकारी एन. एच-12 द्वारा अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 04.06.2010 संयुक्त रूप से जारी किया गया है। खातेदारान के मध्य राशि बाबत विवाद ना होकर स्वामित्व/बंटवारे के संबंध में विवाद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में धारा 3 एच (4) के बिन्दु संख्या 4 में "यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है, के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा। भूमि किसके अधिकार क्षेत्र में स्थित है" का उल्लेख है।

न्यायालय हाजा को "यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है, के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है" तो इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं है। प्रार्थीगण समक्ष न्यायालय में चारा-जोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

मजिस्ट्रेट N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोक (रा.ब.)